ASSOCHAM's request for joining Paris convention

3915. SHRI P. UPENDRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Association of Chamber of Commerce and Industry in India has pleaded for joining the Paris convention; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) and (b) According to the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) it would be in India's interest to join the Paris Convention subject to safeguards to be negotiated. Government has not taken any decision in the matter.

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के विरूद्ध जांच

3916. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कम्पनी लि० के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गई (i) यूनाइटेड किंगडम से फोटो डिस्पेंसिंग यूनिटों (इंडू फोटो मेकर) की खरीद; (ii) श्रव्य परियोजना के लिए मशीनों की खरीद; (iii) पहचान-पत्र प्रणाली के लिए मशीनों की खरीद; (iv) व्यावसायिक प्रयोग के लिए 120 साईज के रोल हेतु एग्फा जम्बो रोल्स की घटिया सामग्री की खरीद; और (v) यूनाइटेड किंगडम से 400 एस.ए. यथा उच्च गति के ए.एस.ए. की खरीद के सम्बन्ध में जांच करने का आदेश दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Irregular entrants on the Posts of Chief executive of some Public Sector undertakings

3917. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in some Public sector Undertakings irrigular entrants have been engaged on the posts of Chief Executive and they have not been removed till now though the companies /corporations have been going worser and worser everyday; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Location of industries

3918. SHRI M. VINCENT : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government propose to take measures to distribute locations of the multinational/NRI, and other large scale industries being set up as a result of the new industrial policy, all over the country and to check their concentration around Delhi ; and

(b) the number of new multinational NRI and other large industries that have been permitted after the change in the Industrial Policy and their respective location, state-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P.J. KURIEN) : (a) The new industrial policy provides freedom to an enterpreneur for locating his project anywhere in India subject to the locational policy of the Government, In cities having more than one million population, a project is required to be located 25 kms. outside the standard urban area limit of these cities. Delhi is one of these cities. Therefore, industries can be set up in Delhi outside the prescribed limit of 25 kms. Location of industrial units is also subject to Central or State environmental laws or regulations including local zoning and land use laws and regulations.

(b) After the announcement of new Industrial Policy, a total number of 319 Letters of Intent have been granted for setting up industries during the period

from 1st August, 1991 to 29th February, 1992. It includes 5 letters of Intent granted in favour of Non-Resident Indians. Details such as name and address of the undertakings, locations, item (s) of manufacture and capacity in respect of Letters of Intent granted are published regularly by the Indian Investment Centre in their 'Monthly News Letter'. Copies of the publication are being sent to the Parliament Library regularly.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति

3919. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान सरकारी क्षेत्र के किन-किन उद्योगों के कितने-कितने व्यक्ति स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्हें कुल कितनी धनराशि का भुगतन किया गया है ?

उद्योग मंत्रयलय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकारी क्षेत्र के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है, निम्नलिखित लाभों के पात्र हैं :—

(i) अंशदान भविष्य निधि विनियमों के अनुसार भुगतान योग्य उसके भविष्य निधि खाते की बकाया राशि ।

(ii) उद्यम के नियमों के अनुसार संचित अर्जित छुट्टी के बराबर नकद धनराशि ।

(iii) कर्मचारी पर लागू उपदान अधिनियम अथवा उपदान योजना के अनुसार उपदान धन राशि ।

(iv) एक माह/तीन माह का सूचना वेतन (उस पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार) ।

(v) पूरे किये गये प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए $1\frac{1}{2}$ माह की परिलब्धियों (वेतन तथा महंगाई-भत्ता जोड़कर) के बराबर अनुग्रह राशि के भुगतान अथवा सेवा-निवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियों को सामान्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व बची हुई सेवा के शेष महीनों से गुणा करके उसके बराबर राशि इनमें से जो भी कम हो ।

(vi) कर्मचारी और उसका परिवार पात्र श्रेणी से उस स्थान तक यात्रा करने का पात्र होगा जहां वह बसना चाहता है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के नाम तथा उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने गत छः महीनों के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है तथा उन्हें अदा की गई कुल राशि के संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्रित किया जाएगा और सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Negative growth rate in Engineering Industry

3920. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether engineering industry has shown a negative growth rate ; if so, the extent thereof and the reasons therefor ; and

(b) the measures Government propose to take to check the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN) : (a) The Engineering Industry has recorded a decline of 6.5% during April-October 1991 over April-October 1990. The negative growth is due to various factors– infrastructural constraints, shortage of raw materials, particularly imported raw material because of foreign exchange constraints, credit squeeze, demand recession in the market, etc.

(b) Government has brought out a Statement on Industrial Policy which was tabled in the Lok Sabha on 24th July, 1991. The New Industrial Policy is aimed at improving industrial production by relaxing controls and removing bureaucratic delays. Many policy measures announced in the Union Budget for 1992-93 are designed to promote industrial growth. Thus, measures like partial